the Annexure to this reply. (*See* Appendix 173, annexure no. 83)

(c) and (d) The details of installed capacity in public (including cooperative) and private sectors during 1992 93, 1993-94 and 1994-95 are given below:

(Figures in 000' tonnes)

Year	Installed capacity in Public/Co-operative Sector		Installed capacity in Private Sector	
	Nitrogen	Phosphate	Nitrogen	Phosphate
1992-93	5908	1101	2623	1721
1993-94	5908	1101	2964	1721
1994-95	5666	1101	3306	1721

In the case of public|cooperative sector, an exercise was carried out during 1994-95 to weed out ob olete|dead capacities. In this process, about 2.4 lakh tonnes of nitrogen capacity was deleted.

(e) Under the Industrial Policy of July, 1991, the fertilizer industry has been delicenced. At present, the installed capacity in the country is 89.72 lakh tonnes of nitrogen and 28.22 lakh tonnes of phosphate. Currently, a number of projects are under implementation and on completion these projects will contribute an additional 14.71 lakh tonnes of nitrogen and 0.31 lakh tonnes of phosphate.

बायो-उर्वरकों का विकास

4080. श्री कनक सिंह मोहनसिंह मंगरोला :

श्री आस मौहम्मद :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बायो-उर्वरकों के विकास के लिये कोई प्रयास किये हैं ; यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान किये गये प्रयासों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) 31 मार्च 1995 तक किन-किन राज्यों के किसानों को विकसित बायो उर्वरक उपलब्ध कर दिये गये है ; और

(ग) समुचित मात्रा में अन्य और उर्वरकों के साथ सही अनुपात में बायो-उर्वरकों के प्रयोग हेतु किसानों को दिये जाने वाले प्रशिक्षण का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) कृषि एवं सहकारिता विभाग "बायो उर्वरकों के विकास तथा प्रयोग पर राष्ट्रीय परियोजना" नामक एक योजना क्रियान्वित कर रहा है । इस परियोजनाओं के तहत, पिछले दो वर्षों के दौरान, किसानों में 21,7,6478 पैकेट (प्रति पैकेट 200 ग्राम का) वितरित किये जा चुके हे । प्रशिक्षण तथा प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं तथा विभिन्न माध्यमों से इसका प्रचार किया गया है । इसके साथ दो वर्षों की अवधि के दौरान, केरल, पश्चिम बंगाल, बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्यो में केन्द्र की सहायता से 8 बायो उर्वरक उत्पादन एकक मंजूर किये गये हैं इसके अलावा, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक राज्यों में नम भूमि चावल में इसके प्रयोग हेतु बा०जी०ए० के उत्पादन के लिये नीले-हर-शैवाल उपकेन्द्रों का सुदृढ़ीकरण किया गया है ।

(ख) राष्ट्रीय / क्षेत्रीय केन्द्रों द्वारा उत्पादित/विकसित बायो उर्वरक उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाट, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, असाम, उत्तर-पूर्वी राज्यों, महाराष्ट्र तथा गोआ राज्यों में किसानों में वितरित किये गए, हैं ।

(ग) जैव-उर्वरक पर राष्ट्रीय परियोजना के तहत, राष्ट्रीय/क्षेत्रीय केन्द्रों ने किसानों में जैव-उर्वरकों के प्रयोग को लोकप्रिय बनाने तथा उसके प्रति जागरूकता पैदा करने के लिये फील्ड, प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये हैं । इस अवधि के दौरान, 134 फील्ड प्रदर्शन संचालित किये गये है तथा 127 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किये गये हैं ।

Subsidy to fertilizer units

4081. SYED SIBTEY RAZI: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether any subsidy has been provided to fertilizer units of country during 1993-94 and 1994-95;

(b) if so, the details thereof unit-wise separately during each year;

(c) whether provision of subsidy to certain units has been found inadequate;

(d) if so, the names of such units;

(e) whether Government propose to increase the subsidy of these units in 1995-96 after thorough study of their need; and

(f) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI EDUARDO FALEIRO): (a) and (b) Details of unit-wise payment of fertilizer subsidy during 1993-94 and 1994-95 are given in the statement to the reply (See below).

(c) Under the Retention Price-cum-Subsidy Scheme (RPS), the difference between the Retention Price of each individual unit (i.e. the cost of production, as assessed by the Government plus reasonable return on networth) and the net realisation from the farmers is paid as subsidy. The amount of subsidy disbursed under the scheme varies from unit to unit depending on factors like retention price of the concerned unit as fixed by the Government, consumer price statutorily fixed by hte Government and production|despatches made by the unit. The scheme does not envisage earmarking of funds for individual units.

(d) to (f) In view of the answer to part (c) above, question does not arise.

Statement

Unit-wise payment of subsidy during the year 1993-94 *and* 1994-95.

(Rs. in crores)

		1993-94	1994-95
1.	yanides & Chemicals Co. Ltd.	0.02	0.03
2.	eepak Fertilizers & Petro-chemical Corporation Ltd.	5.49	18.12
3.	ID Parry (India) Ltd.	—	3.74
4.	ertilizers and Chemicals Travancore Ltd.	99.67	112.35